मृत्युदर की हो चाहे शिशु दर की हो, स्वयं आपने भी ध्यान किया होगा कि दोनों ही क्षेत्रों में पूर्वांचल, जो भारत का हमारा पूरब का इलाका है वह और विशेष तौर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम इसमें आगे हैं। तो एक तो यह जो विशेष क्षेत्र इधर के, उधर के हैं, जैसा सुरेश भाई पचौरी जी ने पूछा, उनके बारे में कोई विशेष प्रकोष्ठ बनाकर आप कोई नई योजना इसमें शामिल करेंगी? दूसरा, जैसा अभी अभी आपने बताया कि पांच हजार की आबादी को आप गांव मानेंगी, जो अगर आप पांच हजार की आबादी को गांव मानती हैं तो भारत का गांव तो बहुत पीछे रह जाएगा। क्या इस आबादी की संख्या को और नीचे ले जाकर आप एक हजार तक की आबादी को गांव मानेंगी ताकि सब दूर रक्षा हो सकें? यह मेरा आपसे आग्रह, निवेदन भी होगा।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी बैरागी जी ने दो पूरक प्रश्न पूछे हैं। पहले तो जो आपने पूछा कि उन राज्यों के बारे में कोई विशेष योजना बनेगी क्या, जहां के आंकड़े खराब हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी एक एमपावर्ड एक्शन ग्रुप, ईएजी के नाम से आठ राज्यों के बारे में बना दिया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नवगठित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल और उड़ीसा को लिया है। इन आठ राज्यों के लिए अलग से एक एमपावर्ड एक्शन ग्रुप बना दिया गया है, जहां विशेष योजना देकर के और विशेष तवज्जुह देकर कार्यक्रम कराए जाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि इनकी विशेष चिंता प्रधानमंत्री जी ने करके इन आठ राज्यों की विशेष बैठक उन्होंने अपनी अध्यक्षता में बुलाई थी। तो इनके लिए विशेष योजना चल रही है। जहां तक आपने कहा कि मैंने पांच हजार की आबादी को गांव माना है, तो मैंने पांच हजार की आबादी को गांव नहीं माना बल्कि मैंने कहा कि पांच हजार की आबादी पर एक सब-सेंटर हो और यह भी बताया कि वर्ष 1991 की सेन्सस के आधार पर ही अगर हम पांच हजार जनसंख्या को सब-सेंटर दें तो हमें अभी 8200 नए सब-सेंटर चाहिएं। अभी तो वर्ष 2001 की सेन्सस के आधार पर पांच हजार की आबादी पर भी सब-सेंटर नहीं पहुंच रहा है तो एक हजार पर पहुंचने में तो समय लगेगा क्योंकि कहीं न कहीं रिसोर्स कन्स्ट्रेंट आड़े आता है।

**267. [The questions (Shri J. Chitharanjan and Shri V.V. Raghavan) was absent for answer vide page 36 infra.]*

पटना के विकास हेतु सहायता

268. **डा० कुमकुम राय:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पटना शहर की समेकित विकास योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह वित्तीय सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) बिहार राज्य जल परिषद्, पटना ने दिनांक 14.9.2002 के अपने पत्र द्वारा पटना के एकीकृत विकास के लिए निम्नलिखित परियोजना रिपोर्टें भेजी हैं जिनमें विदेशी वित्त एजेंसियों से वित्तीय सहायता की मांग की गई है।

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	माडयूल-I की अनुमानित लागत	माडयूल-II की अनुमानित लागत	कुल
1.	पटना नगर के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	159.90	113.10	273.00
2.	पटना शहरी क्षेत्र के लिए सीवरेज परियोजना	198.04	150.05	348.09
3.	पटना नगर की बरसाती पानी निकासी	540.60	381.10	921.70
4.	पटना में कचरा प्रबंधन परियोजना	91.00	36.10	127.10
	कुल	989.54	680.35	1669.89

वर्तमान में विदेशी धन सहायता केवल माडयूल-I के लिए मांगी गई है।

पटना के एकीकृत विकास के लिए बिहार राज्य जल परिषद् (बी आर जे पी) से प्राप्त परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्टों (पी एफ आर) की तकनीकी दृष्टि से इस मंत्रालय द्वारा जांच की गई है और परियोजना रिपोर्टों को संशोधित करने के लिए उपर्युक्त परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्टों पर 18 जनवरी, 2003 को की गई तकनीकी टिप्पणियों को, मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए, बिहार राज्य जल परिषद् योजना आयोग और आर्थिक कार्य विभाग को पहले भेज दिया गया है। संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्टें इस मंत्रालय में अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। पटना नगर के लिए संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट जब भी मंत्रालय में प्राप्त होगी तो उसे विदेशी वित्त-पोषण की संभावना तलाशने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया जाएगा।

Assistance to development of Patna

†*268. SHRIMATI KUM KUM RAI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to provide financial assistance under the integrated development scheme to Patna City;

(b) if so, the details thereof and by when the financial assistance is likely to be provided; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) Bihar Rajya Jal Parishad, Patna *vide* its letter dated 14.9.2002 has forwarded the following project reports for integrated development of Patna seeking financial assistance from external funding agencies:—

(Rs. in crores)

Sl. No.	Name of the Project	Estimated cost of Module-I	Estimated cost of Module-II	Total
1.	Water supply system for Patna town	159.90	113.10	273.00
2.	Sewerage project for Patna urban area	198.04	150.05	348.09
3.	Storm water drainage of Patna town	540.60	381.10	921.70
4.	Solid Waste Management Project in Patna	91.00	36.10	127.10
	TOTAL:	989.54	680.35	1669.89

At present external funding has been sought for module-I only.

The Project Feasibility Reports (PFRs) received from Bihar Rajya

†Original notice of the question was received in Hindi.

Jal Parishad (BRJP) for integrated development of Patna, have been scrutinized from technical angle by this Ministry and technical comments made on 18th January, 2003 on the above PFRs for modifying the project reports have already been forwarded to BRJP, Planning Commission and Department of Economic Affairs for further necessary action in the matter. The modified PFRs are yet to be received in this Ministry. As and when the modified PFRs for Patna town are received in this Ministry the same would be forwarded to the Department of Economic Affairs for exploring the possibility of external funding.

डा॰ कुमकुम राय: माननीय सभापति महोदय, बटवारे के पश्चात् बिहार बेचारा हो गया। आर्थिक स्रोत झारखंड को मिल गए, बिहार के पास बाढ़ और सुखाढ़ आया और इसके साथ-साथ केन्द्र की वक्र दृष्टि का भी उसे शिकार होना पड़ा है। केन्द्र की ओर से वादा-खिलाफी भी की गई क्योंकि वादे के मुताबिक उसे आर्थिक पैकेज भी नहीं मिला। अब बिहार सरकार बिहार की राजधानी, ऐतिहासिक महत्व वाली पाटलीपुत्र, यानि पटना के समेकित विकास की इच्छा रखती है और इसके लिए आज से सात महीने पहले एक परियोजना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी। पटना की उस एकीकृत विकास योजना के लिए बिहार राज्य जल परिषद ने यह जो परियोजना भेजी उसमें आज जो मंत्री महोदय ने हमें उत्तर दिया है, मैं बड़े खेद के साथ आपको बताना चाहती हूं कि इन्होंने सदन को भी गुमराह किया है। इन्होंने कहा है इसमें कि इसमें विदेशी वित्त एजेन्सियों से वित्तीय सहायता मांगी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या वास्तव में बिहार सरकार ने जो परियोजना आपके पास भेजी है, उसमें क्या उन्होंने वित्तीय धन प्राप्त करने की ही अपनी मंशा जताई है?

SHRI ANANTH KUMAR: Sir, this Integrated Project is...*(Interruptions)*...

डा॰ कुसुम राय: सर, हिन्दी में बोलिए। समेकित विकास योजना, एकीकृत विकास योजना। ...**(व्यवधान)**...

SHRI N. JOTHI: When the question was put in English, the Minister was answering in Hindi. So, when the question is put in Hindi, why can't it be answered in English? Interpretation Service is available, so, there should not be any problem.

श्री सभापति: ट्रांसलेशन की व्यवस्था है, आप उसे लगा लीजिए।

श्री अनन्त कुमार: सर, यह प्रोजेक्ट हमने इंटरनेशनल एजेंसी को पोज किया है और जैपनीज बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन के सामने पेयजल और सीवरेज के बारे में तीन ऐसे प्रोजेक्टस-एक बंगलौर का, एक जयपुर का और तीसरा पटना का-मौजूदा हैं और जयपुर व बंगलौर की डिटेल

प्रोजेक्ट रिपोर्ट पिछले साल आ चुकी है, पटना की आनी बाकी है। इसलिए जब वह आएगी तो हम उसको पोज़ करेंगे।

डा० कुमकुम राय: सभापति जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने इनसे पूछा था कि सात महीने पहले बिहार सरकार ने जो परियोजना भेजी थी, क्या उन्होंने सिर्फ वित्तीय सहायता की मांग की थी? यहां उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है और योजना के लिए राशि के जो स्रोत उन्होंने बताए-(क) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (ग) बाह्य वित्त पोषण संस्थान द्वारा भारत सरकार। तो उन्होंने तीसरे में, (ग) में लिखा था बाह्य वित्त पोषण और उन्होंने उत्तर दिया है सिर्फ एक लाइन लिखकर कि इन्होंने विदेशी धन की मांग की थी और इन्होंने अपनी तरफ से और कोई बात इसमें नहीं कही।

इसके साथ ही साथ, महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इन्होंने अपने उत्तर में एक बहुत ही चलता सा जवाब दिया है-''संशोधित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट''। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि पटना में जल के लिए पाइप लाइन बिछानी है, सीवरेज लाइन बिछानी है या जो जल परिषद बनाना है, इसके लिए व्यवहार्यता की रिपोर्ट की क्या परिभाषा है?

श्री सभापति: ठीक है, अब मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री अनन्त कुमार: सर, मेरा सीधा जवाब यह है कि बिहार सरकार ने भारी वित्तीय सहायता के लिए एक परियोजना हमारे सामने रखी है।

डा० कुमकुम राय: सर, यह मेरे पास है, इसको देखा जा सकता है।

श्री सभापति: श्री प्रेम गुप्ता। ये आपकी ही पार्टी के हैं, इनको बोलने दीजिए।

श्री प्रेम गुप्ता: मान्यवर, बिहार के साथ भेदभाव की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। 14.09.2002 को बिहार जल निगम ने अपनी स्कीम भेजी और इन्होंने 18 जनवरी, 2003 को एक लैटर लिख दिया कि इसको मोडिफाई करके भेजिए। उसके बाद आप बोलते हैं कि जब इसका जवाब आएगा तो हम इसको प्लानिंग कमीशन और इक्नॉमिक अफेयर्स के पास रेफर करेंगे। यह तो एक डिले करने की टैक्टिक्स है आपकी। एक रिक्वायरमेंट है वहां पर है और आपको जनता की सुख-सुविधाओं को देखते हुए, ह्यूमेनटेरियन ग्राउंड पर, इसका निवारण करना चाहिए। इसको देखते हुए कि वहां पर सीवरेज की किस तरह से बुरी हालत है, जनसंख्या बढ़ रही है, आपको जल्दी से जल्दी इसका कोई निवारण करना चाहिए। खाली एक लैटर यहां से वहां भेज दिया और वहां से यहां भेज दिया, it is not going to solve the problem. I would like to know from the hon. Minister how they have dealt with the other States, and why they are delaying in the case of Bihar only.

SHRI ANANTH KUMAR: Mr. Chairman, Sir, firstly, I would like to say that there is no delay.

Secondly, this huge project has been posed to international financial agencies, especially, the Japanese Bank of International Cooperation. Last year, they did not allocate any money for urban development. This year, again, we are posing these projects before March 31. ...*(Interruptions)*.... Bangalore and Jaipur had given their prioritised reports last year only. We have been so facilitating the project given by Patna that it has been already prioritised and posed before the JBIC. I seek the cooperation of the hon. Members that they put pressure on the Bihar Government. Not only have we written letters, but meetings between the officers of the Government of India and the officers of the Bihar Government have been held on this issue. They have to come out with modified PFR, so that we can facilitate the entire project.

SHRI PREM CHAND GUPTA: Mr. Chairman, Sir, they have taken four months to acknowledge the letter. They have taken four months for this. And after four months....*(Interruptions)*....

SHRI ANANTH KUMAR: It will take one year for the whole process to begin....*(Interruptions)*....

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय सभापति जी, मंत्री जी का चलता-फिरता जवाब है। दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। एक पत्र वह लिखेंगे, फिर वहां से कोई जवाब आयेगा। फिर ये कहेंगे कि इसको संशोधित करके भेजो। Where there is a will, there is a way.

सभापति महोदय, ये बिहार को कुछ देना नहीं चाहते हैं। इनका बिहार सरकार के प्रति दूजा व्यवहार है। अभी-अभी जैसा डॉ॰ कुमकुम राय ने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद हमको कोई पैकेज नहीं मिला है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। इनका जवाब है कि पटना नगर के लिए संशोधित परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट जब भी मंत्रालय में प्राप्त होगी तो उसे विदेशी वित्तपोषण की संभावना तलाशने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को भेज दिया जाएगा। इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें बिहार राज्य जल परिषद, योजना आयोग और आर्थिक कार्य विभाग के पास पहले भेज दिया गया है, यह इन्होंने कहा है। इनको मंत्रालय चलाने का अनुभव ज्यादा होगा।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वहां से पुन: रिपोर्ट आने के बाद, संभावना तलाशने और सचमुच में वित्तपोषण में कितना समय लगेगा? अगर मंशा ठीक है तो इसके बारे में कृपा करके मंत्री जी बताने का कष्ट करें।

श्री अनन्त कुमार: सर, बिहार की राजधानी पटना के लिए एक हजार करोड़ रुपये की परियोजना है। उस एक हजार करोड़ रुपये की परियोजना में पेयजल, सीवरेज, स्टार्म वाटर ड्रेनेज,

सोलिड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जैसे कई मुद्दे हैं। इसके बारे में हम बिहार जल परिषद के साथ सम्पर्क में हैं। ...(व्यवधान)...

प्रो॰ राम देव भंडारी: क्या सम्पर्क में हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI PREM CHAND GUPTA: They have acknowledged the letter after four months.

श्री सभापति: आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... आप बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए।

श्री अनन्त कुमार: सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय और बिहार जल परिषद सम्पर्क में है। यदि हमको एक हजार करोड़ रुपया चाहिए तो जैपनीज बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन से ही मिलेगा। उन्होंने पहले फेज के लिए 1000 करोड़ रुपया मांगा है। लेकिन अभी इसको हम उनके सामने रखेंगे यानी जैपनीज बैंक आफ इंटरनेशनल कोआपरेशन के सामने रखेंगे और जो कुछ पटना के बारे में और बिहार के बारे में मांगा है, उसको करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी: आप एक अनुमानित समय तो बता दीजिए? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए। आप बैठिए। ऐसे नहीं होगा। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी आप एक काम करिए। आप खतो-किताबत की जगह बिहार के अधिकारियों और मंत्रियों को बुला लीजिए और इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा करा दीजिए।

श्री अनन्त कुमार: सर, ठीक है।

Coverage of Iraq crisis

*269. SHRI SANJAY NIRUPAM:††
SHRI DATTA MEGHE:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Doordarshan has decided to engage a private producer to provide its viewers coverage of the unfolding Iraq crisis;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the owner of this Production House has any outstanding dues to DD; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sanjay Nirupam.